अमेरिका-ईरान विवाद

लेखक -मोहम्मद अयूब (प्रोफेसर, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

द हिन्दू

13 जुलाई, 2019

"पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच टकराव आर्थिक परिणामों को नुकसान पहुंचा सकता है।"

7 जुलाई को, ईरान ने घोषणा की कि वह परमाणु समझौते के तहत 3.67% की अनुमति के साथ यूरेनियम को समृद्ध करना शुरू कर देगा, जिसे संयुक्त व्यापक क्रियान्वयन योजना (जेसीपीओए, JCPOA) के रूप में जाना जाता है, जिस पर 14 जुलाई, 2015 को ईरान और P5+1 (चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका) द्वारा सहमति बनी थी।

इससे पहले 1 जुलाई की घोषणा में कहा गया कि इसने 300 किलोग्राम समृद्ध यूरेनियम भंडार की सीमा, जिसे JCPOA द्वारा अनुमति दी गयी थी, को पार कर लिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि ईरान का धैर्य अब धीरे-धीरे खत्म होने की कगार पर है।

जून में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अमेरिका के एक मानवरहित अमेरिकी ड्रोन को मार गिराने के बाद ही अमेरिका-ईरान के बीच विवाद बढ़ गया है। इस घटना के आस-पास की परिस्थितियों के अनुसार ही ये सारे विवाद आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि, इसने अमेरिकी राष्ट्रपति, डोनाल्ड ट्रम्प को ईरान पर जवाबी हमला करने के लिए प्रेरित किया था, लेकिन अंतिम समय में उन्होंने अपने इस फैसले को वापस ले लिया।

ईरान के साथ पूरे पश्चिम एशियाई क्षेत्र में तबाही फैल सकती है। इसके अलावा, लेबनान, इराक और सीरिया में ईरानी सहयोगियों ने अमेरिकी सेना के साथ-साथ अमेरिकी सहयोगी इजरायल के खिलाफ भी हमले शुरू किए, जिसके बाद ही अमेरिका और इजरायल जवाबी कार्रवाई करने को मजबूर हुए और अमेरिका के लिए यह तीसरे प्रमुख युद्ध के रूप में बन गया।

अमेरिकी-ईरान संबंधों में गिरावट श्री ट्रम्प के निर्णय (मई, 2018 में घोषित) के साथ शुरू हुई, जहाँ ट्रम्प ने यूरोपीय सहयोगियों फ्रांस, जर्मनी और यू.के. की सलाह के खिलाफ जाकर जेसीपीओए से पीछे हटने का फैसला लिया था। ट्रम्प प्रशासन ने ईरान के खिलाफ कड़े आर्थिक प्रतिबंधों को फिर से लागू करने के साथ-साथ इसका पालन किया जो कि 2015 के परमाणु समझौते के बाद धीरे-धीरे खत्म हो रहे थे। इनमें ईरान के साथ व्यापार करने वाली विदेशी कंपनियों के खिलाफ प्रतिबंध और ईरानी तेल खरीदने वाले देशों के खिलाफ प्रतिबंध शामिल थे।

मांगों की सूची

अंत में, अमेरिका ने इस साल अप्रैल में घोषणा की कि वह आठ देशों (चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, तुर्की, इटली और ग्रीस) को दी गई छूट का विस्तार नहीं करेगा, जो ईरानी तेल का सबसे बड़ा आयातक था। यह निर्णय ईरानी तेल के निर्यात पर पूरी तरह से रोक लगाने के उद्देश्य से लिया गया था, जो तेहरान के लिए प्राथमिक विदेशी मुद्रा अर्जक वाले क्षेत्र में से एक था, ताकि ईरान को अपने घुटनों पर लाया जा सके और अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ द्वारा लिखित अमेरिकी मांगों को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जा सके।

इनमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अंकुश लगाना शामिल था, जिसमें जेसीपीओए द्वारा अनुमति दिए गए निम्न स्तर पर यूरेनियम संवर्धन पर रोक और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा निगरानी शामिल थी।

इसके अलावा, श्री पोम्पियो ने मांग की थी कि ईरान हिजबुल्लाह और हमास के सभी समर्थन को रोक दे, जिसे अमेरिका 'आतंकवादी' समूह मानता है, इराक में शिया मिलिशिया के निरस्त्रीकरण की अनुमति दे और उस देश में सऊदी एवं अमीरात सेना से लड़

रहे यमन में हदीसियों का समर्थन करना बंद कर दे। इन सबसे ऊपर, श्री पोम्पियो ने मांग की कि ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों का निर्माण और परमाणु सक्षम मिसाइल प्रणालियों के विकास या लॉन्चिंग को रोक दे।

ये सभी मांगें जेसीपीओए द्वारा ईरान पर रखी गई सीमाओं से बहुत आगे निकल गई थी और अधिकांश ईरान के परमाणु कार्यक्रम से असंबंधित थीं। ईरान सरकार ने इन मांगों को खारिज कर दिया। हांलाकि, अभी भी बातचीत के लिए दरवाजा खुला है और यह उम्मीद की जा रही है कि अमेरिका फिर से परमाणु समझौते में वापस शामिल हो जाएगा।

हालांकि, पिछले वर्ष के दौरान यू.एस. के लगातार और बढ़ते कदम ने यह लगभग तय कर दिया है कि ईरान और अमेरिका संबंध फिर से जीवित हो पाएगा, साथ ही साथ जेपीसीओए द्वारा अपने परमाणु कार्यक्रम पर लगाए गए प्रतिबंधों का पालन करते हुए अमेरिकी मांगों का विरोध करने की विरोधाभासी स्थिति को बनाए रखना है।

हाल की अमेरिकी कार्रवाईयों के आलोक में ईरान की हसन रूहानी सरकार का रुख लगातार अस्थिर होता गया। उत्तरार्द्ध ने ईरान में कट्टरपंथी विरोध को जन्म दिया। इसके अलावा, ईरानी सुप्रीम लीडर, अयातुल्ला अली खामेनेई, जिनका JCPOA के लिए समर्थन महत्वपूर्ण था, ने सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए राष्ट्रपति रूहानी और ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ की जोड़ी को बिना किसी सुरक्षात्मक राजनीतिक कवर के समझौते में अपने समर्थन को वापस ले लिया।

जैसे को तैसा उपाय

इसलिए, ईरानी सरकार, आबादी के साथ अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए, फारस की खाड़ी में राजनीतिक तापमान को और अधिक बढ़ाने के अलावा, कोई विकल्प नहीं छोड़ती है। इसने अमेरिकी-ईरान गतिरोध को गेम ऑफ चिकन के खेल में बदल दिया है, जिसमें या तो गेम में से कोई एक बहुत गंभीर स्थिति में पहुँच जाता है या दोनों का अस्तित्व खत्म हो जाता है। अमेरिकी-ईरानी टकराव को आने वाले दिनों में और अधिक बढ़ने की उम्मीद है। अगर इसे तार्किक निष्कर्ष पर ले जाया जाए, तो यह परिदृश्य पूरे पश्चिम एशियाई क्षेत्र के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए भी विनाशकारी हो सकता है।

GS World टीम...

अमेरिका-ईरान के बीच बढ़ता विवाद

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में ईरान ने 2015 के परमाणु समझौते में संवर्धित यूरेनियम के उत्पादन को लेकर तय की गई सीमा का उल्लंघन किया और यूरोप को जवाबी कार्रवाई करने के खिलाफ आगाह किया।
- इसके साथ ही माना जा रहा है कि ईरान पी5+1 और यूरोपीय संघ के साथ 2015 में हुए ऐतिहासिक समझौते को तोड़ने की दिशा में आगे बढ़ गया है, जिस दौरान यूरेनियम भंडारण की सीमा तय की गई थी।
- गौरतलब हो कि ईरान ने मई में घोषित अपनी योजना के आधार पर 300 किलोग्राम की सीमा पार कर ली है।
- ईरान द्वारा निर्धारित सीमा (3.7%) को पार किए जाने और 4.5 प्रतिशत संवर्धन करने की घोषणा देश के परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रवक्ता बेहरूज कमालवंदी ने की।
- कमालवंदी ने संकेत दिया है कि इस्लामी गणराज्य कुछ समय तक संवर्धन के इस स्तर को बरकरार रख सकता है, जो एक परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी 90 प्रतिशत के स्तर से काफी नीचे है।

पृष्ठभूमि

- अमेरिका ने पिछले साल परमाणु सौदे से खुद को अलग कर लिया था और ईरान के महत्त्वपूर्ण तेल निर्यात और वित्तीय लेन-देन तथा अन्य क्षेत्रों पर सख्त प्रतिबंध फिर से लगा दिए थे।
- ईरान, जिसने समझौते को बचाने के लिए इसके अन्य साझेदारों पर दवाब बढ़ाने की कोशिश के तहत घोषणा की थी कि वह संवर्धित यूरेनियम एवं हैवी वाटर भंडार पर लगाई गई सीमा को अब नहीं मानेगा।
- साथ ही धमकी दी थी कि वह और परमाणु प्रतिबद्धताओं को भी नहीं मानेगा जब तक कि समझौते के शेष साझेदार- ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, जर्मनी और रूस इन प्रतिबंधों से उसे छुटकारा नहीं दिलाते, खासकर तेल की बिक्री पर लगे प्रतिबंध से।

- वर्ष 2015 में हुए इस सौदे के तहत ईरान ने कभी भी परमाणु बम नहीं रखने, उसके परमाणु कार्यक्रम पर लगाई गई कठोर सीमाओं को मानने और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को आंशिक रूप से हटाए जाने के बदले में आईएईए को निरीक्षण करने देने की प्रतिबद्धता जताई थी।

होर्मुज जलडमरूमध्य

- इसे ओरमुज जलडमरूमध्य के नाम से भी जाना जाता है। यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है।
- यह ईरान को अरब प्रायद्वीप से अलग करता है और यह 55 से 95 किमी. तक चौड़ा है।
- इसमें प्रमुख रूप से कीश्म, होर्मुज और हेंजम (हेंग्म) द्वीप स्थित हैं।
- सऊदी अरब, ईरान, यू.ए.ई., कुवैत और इराक से निर्यात किये जाने वाले अधिकांश कच्चे तेल को इसी जलमार्ग के माध्यम से भेजा जाता है।

संयुक्त व्यापक क्रियान्वयन योजना (JCPOA)

- ईरान के परमाणु कार्यक्रमों पर नजर रखने के लिये वर्ष 2015 में ईरान तथा P5+1 देशों (अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्राँस, रूस और जर्मनी) के मध्य एक समझौता किया गया। इसे वियना समझौता के नाम से जाना जाता है।
- इसके अनुसार ईरान अपने परमाणु संयंत्रों की नियमित जाँच के लिये राजी हुआ, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि वहाँ परमाणु हथियार बनाने पर काम नहीं चल रहा है।
- इस समझौते में ईरान द्वारा परिष्कृत यूरेनियम भंडार को 96 प्रतिशत तक घटाना और अपने सभी संयंत्रों को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों के लिये खोलना शामिल है।
- इस समझौते के तहत ईरान ने अपने करीब नौ टन अल्प संवर्द्धित यूरेनियम भंडार को कम करके 300 किलोग्राम तक करने की शर्त स्वीकार की थी।
- इस समझौते का मकसद परमाणु कार्यक्रमों को रोकना था। इन शर्तों के बदले में पश्चिमी देश ईरान पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध हटाने पर सहमत हुए थे।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1- gkeqt tyMe:eè; d lnHk e fuEufyf[kr dFkuk ij fopkj dhft,%

1. यह फारस की खाड़ी को, ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है।
2. कीश्म और हेंजस जैसे द्वीप भी यहीं पर अवस्थित हैं।

उपर्युक्त में से कौन–सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

Expected Questions (Prelims Exams)

1. In the context of Hormuz Strait, consider the following statements-

1. It connects the Gulf of Persia with the Gulf of Oman and Arabian Sea.
2. Kishm and Henzum like islands are situated here.

Which of the above statement is/are correct?

(a) Only 1 (b) Only 2
(c) Both 1 and 2 (d) Neither 1 nor 2

Expected Questions (Mains Exams)

प्रश्नः अमेरिका और ईरान के बीच विवाद के प्रमुख बिन्दुओं की चर्चा करते हुए इससे वैश्विक जगत पर पड़ने वाले प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। **(250 शब्द)**

Q. Discussing the main points of disputes between America and Iran explain the effects of it at global level. **(250 Words)**

नोट : 12 जुलाई को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c) होगा।